24 न्यूज अपडेट

ई-न्यूज

WebSite.: https://24newsupdate.in

Mail Id :desk24newsupdate@gmail.com

उदयपुर, गुरूवार 25 दिसम्बर 2025

वर्ष 2 अंक 234

अब आप टोल कलेक्शन से भी मुनाफा कमा सकेंगे: NHAI के राजमार्ग ट्रस्ट को सेबी की मंजूरी; निवेश पर मिल सकता है 10% तक रिटर्न

24 न्यूज अपडेट

अब आप देश के नेशनल हाईवे में पैसा लगाकर मुनाफा कमा सकेंगे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की नई पहल 'राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट' (RIIT) को बाजार नियामक सेबी (SEBI) से मंजूरी मिल गई है। यह स्कीम आम लोगों को नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने का मौका देगी, जहां रिटेल और घरेलू इन्वेस्टर्स सीधे हिस्सा ले सकेंगे।

जिस तरह आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसी तरह अब आप सड़कों में पैसा लगा पाएंगे और गाड़ियों से वसूले जाने वाले टोल टैक्स की कमाई में आपको हिस्सा मिलेगा। ये स्कीम भारत के अन्य इनविट स्कीम्स की तरह 10% तक रिटर्न दे सकती है।

आम निवेशक को सरकारी भरोसे का फायदा

अभी तक हाईवे और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में सिर्फ बड़ी कंपनियां या विदेशी निवेशक ही पैसा लगा पाते थे। लेकिन इस 'पब्लिक इनविट' का मुख्य मकसद रिटेल इनवेस्टर (आम निवेशक) को जोड़ना है।

रेगुलर इनकमः इनविट से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा डिविडेंड के रूप में निवेशकों को बांटा जाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो बैंक FD से थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहते हैं।

सरकारी भरोसाः यह NHAI का प्रोजेक्ट है, इसलिए इसमें सरकारी सुरक्षा ज्यादा है।

लंबी अवधि का निवेशः यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टूल है, जो आपको लंबे समय तक रिटर्न दे सकता है।

ये स्कीम कैसे काम करेगी?

इसे आप एक 'रेंटल इनकम' की तरह समझ सकते हैं। आप इनविट की यूनिट्स (शेयर की तरह) खरीदते हैं। यह ट्रस्ट उस पैसे से बनी-बनाई सड़कों को सरकार से लीज पर लेता है या मैनेज करता है।

उन सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों से जो 'टोल टैक्स' मिलता है, वह ट्रस्ट की कमाई होती है। खर्चे काटकर बाकी मुनाफा यूनिट होल्डर्स (यानी आप) में बांट दिया जाता है।

10 बड़े बैंक पैसा मैनेज करेंगे

आपके निवेश की सुरक्षा और मैनेजमेंट के लिए NHAI ने 'राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड' (RIIMPL) नाम से कंपनी बनाई है। इसमें देश के 10 सबसे बड़े और भरोसेमंद वित्तीय संस्थान भागीदार हैं। यानी आपका पैसा एक्सपर्ट्स की निगरानी में रहेगा।

इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नेशनल बैंक (PNB), एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक, बजाज फिनसर्व वेंचर्स और NABFID (नैशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट) शामिल हैं। NHAI के मेंबर (फाइनेंस) एनआरवीवीएमके राजेंद्र कुमार इस इनवेस्टमेंट मैनेजर कंपनी के एमडी और सीईओ (एडिशनल चार्ज) होंगे।

निवेश कैसे कर पाएंगे?

चूंकि यह एक लिस्टेड इनविट होगा, इसलिए इसमें निवेश करने के लिए आपके पास 'डीमैट अकाउंट' होना जरूरी है। जब इसका IPO (इनिशियल पब्लिक ऑफर) आएगा, तब आप अपने ब्रोकर एप (जैसे जीरोधा, ग्रो एंजल वन आदि) के जरिए इसमें बोली लगा सकेंगे। लिस्ट होने के बाद आप शेयर बाजार से भी इसकी यूनिट्स खरीद-बेच सकेंगे।

इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट (इनविट) म्यूचुअल फंड की तरह ही एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है। जैसे म्यूचुअल फंड में लोगों से पैसा लेकर शेयर बाजार में लगाया जाता है, वैसे ही इनविट में लोगों से पैसा लेकर सड़क, बिजली या अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाता है।

भारत में पेट्रोल पंप की संख्या 1 लाख पारः अमेरिका-चीन के बाद तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल नेटवर्क, 90% पंप सरकारी कंपनियों के पास

24 न्यूज अपडेट

भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फ्यूल रिटेल मार्केट बन गया है। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (PPAC) की रिपोर्ट के अनुसार, नवंबर अंत तक देश में पेट्रोल पंप की संख्या 1,00,266 पहुंच गई है।

पेट्रोल पंप नेटवर्क के मामले में भारत अब अमेरिका और चीन से पीछे है। राजमार्गों और ग्रामीण इलाकों में बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए सरकारी और निजी कंपनियों ने पिछले एक दशक में अपना नेटवर्क करीब दोगुना कर लिया है।

अमेरिका में सबसे ज्यादा फ्यूल स्टेशन

दुनिया में सबसे बड़ा पेट्रोल पंप नेटवर्क अमेरिका का है। अमेरिका में पेट्रोल पंप की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में खुदरा पेट्रोल पंप की संख्या 1,96,643 थी। तब से कुछ पंप बंद हो चुके होंगे।

वहीं, पिछले साल एक रिपोर्ट में चीन में पेट्रोल पंप की संख्या 1,15,228 बताई गई थी। चीन की कंपनी चाइना पेट्रोकेमिकल कॉरपोरेशन (सिनोपेक) 30,000 से ज्यादा पंपों के साथ वहां की सबसे बड़ी रिटेलर है, लेकिन भारत की IOC का नेटवर्क (41,664 पंप) सिनोपेक से भी कहीं बड़ा है।

भारतीय सेना में जवानों पर पांच साल बाद सोशल मीडिया की पाबंदी हटाई, नई गाइडलाइन जारी

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। भारतीय सेना ने पांच साल बाद जवानों और अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया एप्स का इस्तेमाल फिर से अनुमति दे दी है। यह आदेश 2020 में सुरक्षा कारणों से लगाए गए बैन को हटाने के बाद जारी नई गाइडलाइन के तहत आया है। पूर्व सेनाध्यक्ष के अनुसार, यह कदम जवानों के लिए सुरक्षित और नियंत्रित डिजिटल माहौल सुनिश्चित करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है। एनआई न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, नई गाइडलाइन में जवान अब इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो देख सकेंगे, लेकिन कमेंट करने की अनुमति नहीं है।

अन्य प्लेटफॉर्म्स की नई नियमावलीः वॉट्सएप, टेलीग्रामः गैर-गोपनीय जानकारी शेयर कर सकेंगे। यूट्यूब और Xः केवल सूचना और जानकारी के उद्देश्य से इस्तेमाल संभव। लिंक्डइन, स्काइप और सिग्नलः नई गाइडलाइन के अनुसार नियंत्रित उपयोग। पूर्व सेनाध्यक्ष ने बताया कि 2020 में सोशल मीडिया एप्स पर कठोर प्रतिबंध इसलिए लगाया गया था क्योंकि हनीट्रैप के कई मामले सामने आए थे। इसके जरिए पाकिस्तान और चीन जैसी पड़ोसी देश सेना के संवेदनशील डेटा और सीमा सुरक्षा की जानकारी जुटा रहे थे। 2020 में सरकार ने 89 एप्स पर बैन लगाया था, जिनमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जूम और पबजी शामिल थे। एप्स के माध्यम से संवेदनशील सूचनाएं लीक होने का खतरा था। सेना ने 2024 में अधिकारियों और जवानों को वॉट्सएप समेत अन्य सोशल मीडिया पर आधिकारिक कामकाज में शामिल नहीं होने की सलाह दी थी। पूर्व सेनाध्यक्ष ने कहा, "सोशल मीडिया का नियंत्रित और सुरक्षित उपयोग जवानों के लिए जरूरी है। नई गाइडलाइन में यह सुनिश्चित किया गया है कि जवानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ते हुए सुरक्षा और गोपनीयता का उल्लंघन न हो।

नाथद्वारा में कार की टक्कर से बाइक चालक की मौत, मकान की दीवार तोड़ी

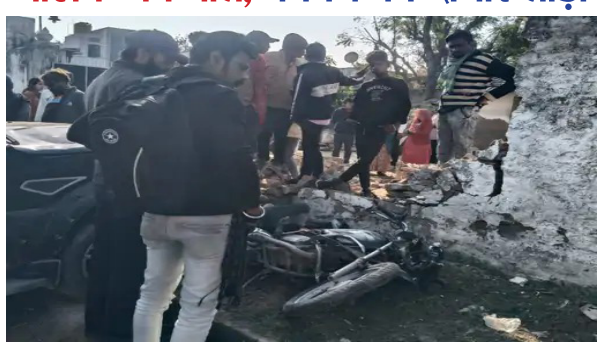

24 न्यूज अपडेट

राजसमंद। राजसमंद जिले के नाथद्वारा में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना श्रीनाथजी मंदिर थाना क्षेत्र में नाथद्वारा–बागोल मार्ग पर घटी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, उसरवास गांव का रहने वाला जगदीश रेबारी (30) सुबह अपने बाइक से नाथद्वारा की ओर जा रहा था। तभी नाथद्वारा की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार की गति अत्यधिक तेज थी। टक्कर के बाद बाइक और चालक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। वहीं, बेकाबू हुई कार सड़क किनारे बने मकान की दीवार से टकराकर अंदर घुस गई। हादसे में बाइक सवार जगदीश लहूलुहान हो गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद श्रीनाथजी मंदिर थाना इंचार्ज विक्रम सिंह और टीम तुरंत मौके पर पहुंचे और जाब्ते के साथ दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने मृतक का शव नाथद्वारा अस्पताल की मॉर्च्युरी में रखवाया और स्कॉर्पियो कार को जब्त कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

भारत के $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य की राह में चुनौती, विशेषज्ञों ने जताई चेतावनी

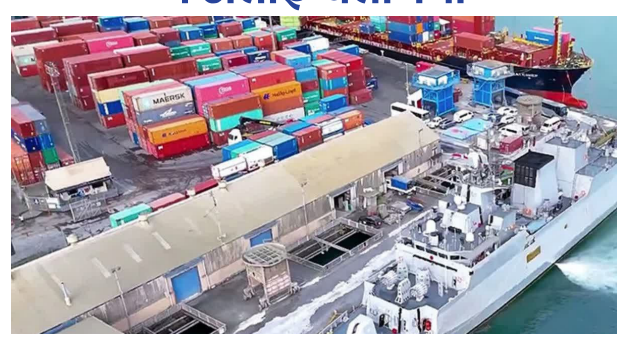

24 न्यूज अपडेट

बल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (GTRI) के अनुसार, भारत वित्तीय वर्ष 2026 (FY26) में माल और सेवाओं के $1 ट्रिलियन निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने से काफी पीछे रह सकता है. वैश्विक मंदी, कमजोर डिमांड और बढ़ते संरक्षणवाद के कारण भारतीय सामान के निर्यात पर दबाव बढ़ा है.

GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने एएनआई से बातचीत में कहा, "हम लगभग वहीं हैं. पिछले साल माल और सेवाओं का कुल निर्यात लगभग $825 बिलियन था. इस साल सामान के निर्यात में लगभग कोई वृद्धि नहीं होगी, जबकि सेवाओं में मामूली बढ़ोतरी होगी. ऐसे में FY26 में कुल निर्यात लगभग $850 बिलियन तक रहेगा. हम $1 ट्रिलियन के लक्ष्य से $150 बिलियन पीछे रह जाएंगे."

उन्होंने कहा कि यह लक्ष्य तभी पूरा हो सकता है जब भारत अमेरिका और यूरोपीय संघ जैसे प्रमुख देशों के साथ बड़े व्यापार समझौते करे. यह संभवतः अगले साल हो सकता है, इस साल नहीं,

हालांकि कुल निर्यात वृद्धि धीमी रही है, भारत के ट्रेड डेटा में निर्यात बाजारों में प्रारंभिक विविधीकरण के संकेत दिख रहे हैं. श्रीवास्तव के अनुसार, मई से नवंबर के बीच अमेरिका को निर्यात में 20.7% की गिरावट आई, लेकिन बाकी दुनिया को निर्यात में 5.5% की बढ़ोतरी हुई.

उन्होंने चेतावनी दी कि नए बाजारों में विस्तार तब तक पर्याप्त नहीं होगा जब तक भारत अपनी निर्यात बास्केट में भी विविधीकरण नहीं करता. श्रीवास्तव ने कहा, "अधिक विविधीकरण के लिए हमें मध्यम और उच्च तकनीकी उत्पादों को अपनी निर्यात सूची में शामिल करना होगा."

BRICS के बारे में उन्होंने कहा, "यह यूरोप या ASEAN जैसी कोई संस्था नहीं है. यह LOOSELY देशों का समूह है और इसका एजेंडा काफी हद तक चीन द्वारा संचालित है. भारत केवल सीमित एजेंडे का पालन करता है."

रुपये पर दबाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह वैश्विक मॉनेटरी स्थितियों और विशेषकर अमेरिका की ब्याज दरों से प्रभावित है. मजबूत निर्यात इससे मुद्रा पर दबाव कम कर सकता है.

श्रीवास्तव ने WTO में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया. "पिछले 25 सालों में WTO में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को छोड़कर कुछ भी सार्थक नहीं हुआ. भारत को WTO सदस्यों से ट्रेड एजेंडे पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह करना चाहिए."

अंत में उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था अभी मजबूत है. GDP और कम महंगाई के आंकड़े इसे दिखाते हैं. "FY26 में GDP पर मुख्य दबाव सिर्फ निर्यात की स्थिति से होगा,"

RBI ने 3 घंटे में क्लियरेंस सिस्टम को किया स्थगित, नई तारीख बाद में घोषित होगी

24 न्यूज अपडेट

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने चेक क्लियरेंस प्रक्रिया को और तेज करने वाली फेज-2 स्कीम को स्थगित कर दिया है। यह योजना 3 जनवरी 2026 से लागू होने वाली थी, जिसमें बैंकों को चेक की इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर अप्रूव या रिजेक्ट करना था। अब इसे आगे की तारीख तक टाल दिया गया है। RBI ने 24 दिसंबर 2025 को सर्कुलर जारी कर बताया कि फिलहाल फेज-1 प्रणाली ही जारी रहेगी। इसके तहत चेक

प्रेजेंटेशन विंडो सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक खुली रहेगी, जबकि बैंक सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक चेक को कंफर्म या रिजेक्ट कर सकते हैं।

फेज-1 में क्या बदलाव हुआ था

फेज-1 की शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को हुई थी। इसके तहत पुराने बैच सिस्टम को हटाकर 'कंटीन्यूअस क्लीयरेंस एंड सेटलमेंट' (CCS) शुरू किया गया था। अब बैंक चेक को स्कैन कर उसकी इमेज तुरंत क्लीयरिंग हाउस को भेजते हैं। चेक बैंक में आते ही प्रोसेस शुरू हो जाता है और यदि तय समय में बैंक कोई कार्रवाई नहीं करता, तो चेक को स्वतः अप्रूव माना जाता है।

फेज-2 में क्या होने वाला था

फेज-2 का उद्देश्य चेक क्लीयरेंस को रियल टाइम के करीब लाना था। इसके तहत बैंकों को चेक इमेज मिलने के 3 घंटे के भीतर अप्रूव या रिजेक्ट करना आवश्यक था। यदि बैंक इस समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं करता, तो सिस्टम ऑटोमैटिकली चेक पास कर देता, जिससे ग्राहक को तुरंत धन प्राप्त हो जाता। RBI ने स्पष्ट किया है कि फेज-2 लागू करने की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी।

संपादकीय : सांसों पर आफत

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हर साल सर्दियां आते ही यहां के बाशिंदों की सांसों संकट मंडराने लगता है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद यहां की वायु स्वच्छ नहीं हो पा रही है। हवा में घुलता प्रदूषण का जहर आमजन की सेहत पर भारी पड़ रहा है। हालत यह है कि मंगलवार को दिल्ली का वायु गणवत्ता सूचकांक चार सौ अंक पार कर गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली से सटे नोएडा की पहचान तो देश के सबसे प्रदूषित शहर के रूप में की गई। दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बुधवार को इस पर चिंता जताई और कहा कि ऐसी आपात स्थिति' में सरकार को वायु साफ करने वाले उपकरणों (एअर प्यूरीफायर) पर कर में छूट देने को लेकर विचार करना चाहिए। इसके लिए जीएसटी परिषद को जल्द से जल्द बैठक बुलाने का निर्देश दिया गया। ऐसे में सवाल है कि आखिर शासन एवं प्रशासन प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए कोई स्थायी एवं प्रभावी योजना लागू क्यों नहीं कर पा रहे हैं ? इस बात पर गौर करना भी जरूरी है कि जो उपाय लागू किए गए हैं, क्या व्यावहारिक रूप से अमल हो पा रहा है या नहीं । यह लंबे समय से बहस का विषय रहा है कि आखिर दिल्ली में प्रदूषण क्यों बढ़ रहा है। इसके लिए कभी पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है, तो कभी दिल्ली-एनसीआर में बढ़ती वाहनों की संख्या तथा उद्योग और निर्माण एवं ध्वस्तीकरण कार्यों को वजह बताया जाता है। मगर इन दिनों तो पराली जलाने की घटनाएं भी बहुत कम सामने आ रही है, फिर दिल्ली की वायु गुणवत्ता का स्तर गंभीर श्रेणी तक कै से पहुंच रहा है! जाहिर है कि इसके पीछे कोई एक वजह नहीं हो सकती, इसलिए प्रदूषण के सभी स्रोतों का ईमानदारी से आकलन करने की जरूरत है। दूसरा, यह सवाल भी महत्त्वपूर्ण है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के सुझाव पर अगर वायु साफ करने वाले उपकरणों पर सरकार जीएसटी में छूट दे देती है, तो इसका लाभ भी आर्थिक रूप से सक्षम तबके तक ही सीमित रहेगा। बाकी आम लोगों को तो जहरीली हवा में ही सांस लेना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य की चिंता कौन करेगा। जबकि इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय अपने एक आदेश में कह चुका है कि स्वच्छ हवा पर सभी नागरिकों का अधिकार है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का एक पहलू यह भी है कि मूल समस्या की जड़ तक जाने की बजाय इस पर राजनीति ज्यादा हावी होने लगी है। सियासी दल अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही से पल्ला झाड़ने के लिए एक- दूसरे पर ठीकरा फोड़ते रहते हैं। दिल्ली में सत्तारूढ़ दल भाजपा का तर्क है कि आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम नहीं उठाए गए। वहीं, आम आदमी पार्टी का कहना है कि भाजपा अपनी जवाबदेही से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के आरोप लगा रही है। सवाल है कि क्या इस तरह के आरोप-प्रत्यारोप से प्रदूषण की गंभीर होती समस्या का समाधान निकल पाएगा? जहरीली हवा की वजह से जो लोग विभिन्न बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार है। समय आ गया है कि मानव जीवन की रक्षा को सर्वोपरि मानकर प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सामूहिक प्रयास किए जाएं, ताकि सभी नागरिक स्वच्छ हवा में सांस ले सकें।

लापरवाही का धुआं

आमतौर पर होटलों में ठहरने के दौरान यह उम्मीद की जाती है कि वहां सुकून के साथ सुरक्षित माहौल भी होगा। मगर देश भर के कई होटलों में जिस तरह की लापरवाही बरती जाती है, वह चिंताजनक है। सुरक्षा के बुनियादी इंतजाम न होने के कारण कई दफा लोगों की जान तक चली जाती है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में ऐसी ही एक घटना सामने आई है। यहां एक होटल में सोमवार रात अंगीठी के धुएं के कारण पांच लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। ये सभी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से इस होटल में रंग-रोगन संबंधी कार्य के लिए आए थे और वहीं एक कमरे में ठहरे थे । यह आश्चर्य की बात है कि इस होटल के कमरे में अंगीठी का इस्तेमाल हो रहा था। ऐसे में सवाल है कि अंगीठी का बंदोबस्त होटल प्रबंधन ने ही किया था या फिर इन लोगों ने अपने स्तर पर इसका इंतजाम किया ? और अगर निजी तौर पर वहां अंगीठी लाई गई थी, तो कर्मचारियों ने उन्हें रोका क्यों नहीं यहां तक कि कमरे से उठते धुएं पर भी ध्यान न देना गंभीर लापरवाही की ओर इशारा करता है। होटलों में प्राथमिक सुविधाओं के साथ सुरक्षा संबंधी बंदोबस्त की जांच करना स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। गौरतलब है कि धुएं और आग की चेतावनी देने वाले उपकरण आमतौर पर कर्मचारियों को सचेत कर देते हैं। ऐसे में सवाल है कि इस होटल में क्या जरूरी सुरक्षा उपकरण नहीं लगाए गए थे ? इस तरह की व्यवस्थागत खामी के लिए होटल प्रबंधन के साथ-साथ वे अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, जो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में समय-समय पर सुरक्षा उपायों का निरीक्षण करते हैं। कुरुक्षेत्र में हुए हादसे को टाला जा सकता था, अगर वहां तैनात कर्मचारी सचेत रहते और सुरक्षा माकूल इंतजाम किए गए होते। लापरवाही के इस धुएं में पांच लोगों के जीवन की लौ बुझ गई, तो इसका दोषी कौन है ? इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए सरकार और प्रशासन को व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर ठोस कदम उठाने होंगे।

इलाज के बीच हमला: कनक हॉस्पिटल में भर्ती युवक ने युवती पर चालाई कैंची

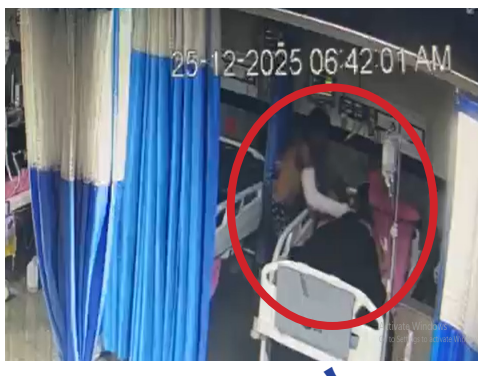

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। उदयपुर के हिरणमगरी क्षेत्र स्थित कनक हॉस्पिटल में गुरुवार को उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब इलाज के लिए भर्ती एक युवक ने अचानक हिंसक रूप अपनाते हुए पास के बेड पर भर्ती युवती पर कैंची से जानलेवा हमला कर दिया। अस्पताल जैसे सुरक्षित माने जाने वाले परिसर में हुई इस सनसनीखेज वारदात से मरीजों और उनके परिजनों में दहशत फैल गई। पुलिस और अस्पताल सूत्रों के अनुसार, घटना वार्ड के भीतर उस समय हुई जब आसपास अन्य मरीज और उनके परिजन मौजूद थे। आरोपी युवक ने अचानक युवती पर ताबड़तोड़ वार शुरू कर दिए। हमले के दौरान युवती की चीख-पुकार सुनकर वार्ड में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थिति बिगड़ती देख अस्पताल स्टाफ और मौजूद लोगों ने साहस दिखाते हुए तुरंत हस्तक्षेप किया और आरोपी युवक को काबू में लिया। इसके बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही हिरणमगरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई कैंची को भी जब्त कर लिया है। इधर, गंभीर रूप से घायल युवती को तत्काल इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है। चिकित्सकों के अनुसार युवती की हालत गंभीर बनी हुई है, हालांकि फिलहाल वह खतरे से बाहर बताई जा रही है।

घटना के बाद अस्पताल परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस यह जांच कर रही है कि आरोपी युवक के पास कैंची कैसे और किन हालात में पहुंची, साथ ही यह भी पता लगाया जा रहा है कि आरोपी और युवती के बीच कोई पूर्व परिचय या विवाद था या नहीं। हिरणमगरी थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है।

आयड़ नदी में मिला अज्ञात युवक का शव

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। प्रतापनगर थाना क्षेत्र से बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब आयड़ नदी में एक व्यक्ति का शव दिखाई देने की सूचना सामने आई। घटना सुखानाका–कानपुर क्षेत्र की है, जहां नदी के बीच झाड़ियों में शव फंसा होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग की टीमें तुरंत सक्रिय हो गईं। सुबह करीब 11 बजे पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि आयड़ नदी में एक व्यक्ति के डूबने की आशंका है। सूचना मिलते ही नागरिक सुरक्षा विभाग की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और तुरंत तलाशी व बचाव अभियान शुरू किया। नदी में पानी और घनी झाड़ियों के बीच शव फंसा होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन चुनौतीपूर्ण रहा। करीब दस मिनट की कड़ी मशक्कत के बाद नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने झाड़ियों में फंसे अज्ञात व्यक्ति के शव को बाहर निकाला। रेस्क्यू पूरा होते ही शव को प्रतापनगर थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। प्रतापनगर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्ट और अन्य पहलुओं को खंगाल रही है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता लगाया जा सके। पूरे ऑपरेशन में नागरिक सुरक्षा विभाग के वाहन चालक मुकेश सेन सहित टीम सदस्य महेंद्र सिंह मसानी, बने सिंह गुर्जर, कैलाश गमेती और रवि शर्मा की अहम भूमिका रही, जिन्होंने समय पर कार्रवाई कर शव को बाहर निकालने में सफलता हासिल की।

लेक सिटी में क्रिसमस की रोशनी, चर्चों की प्रार्थनाओं से बाजारों तक फैला उल्लास

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। झीलों की नगरी उदयपुर क्रिसमस के उल्लास और आध्यात्मिक वातावरण में पूरी तरह रंगी हुई है। सर्द मौसम के बीच शहर की फिजा में कैरोल की मधुर धुनें घुल गई हैं। चर्चों में प्रार्थनाओं, रोशनी और सांस्कृतिक आयोजनों ने लेक सिटी को खास उत्सवी पहचान दे दी है। पर्यटन सीजन के चलते इस बार क्रिसमस का उत्साह और भी अधिक नजर आ रहा है। शहर के प्रमुख चर्चों—शेफर्ड मेमोरियल चर्च, सेंट पॉल्स चर्च, सेंट मेरीज़ चर्च, सेंट ग्रेगरी चर्च, सेंट जॉर्ज चर्च, सेंट जॉन्स चर्च, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (सीएनआई) परिसर और कैथोलिक चर्च परिसर—में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की गईं। सभी चर्चों को आकर्षक रोशनी, क्रिसमस ट्री, स्टार और सजावटी प्रतीकों से सजाया गया। प्रार्थना सभाओं के दौरान कैरोल सिंगिंग की गूंज ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक, शांत और उल्लासपूर्ण बना दिया। बड़ी संख्या में ईसाई समुदाय के लोग अपने परिवारों के साथ चर्च पहुंचे और प्रेम, भाईचारे व शांति का संदेश दिया। क्रिसमस की रौनक धार्मिक स्थलों तक सीमित नहीं रही। उदयपुर के लक्जरी होटलों और रिसॉर्ट्स में क्रिसमस थीम पर विशेष कार्यक्रम और पार्टियों का आयोजन किया गया। इनमें स्थानीय नागरिकों के साथ देश-विदेश से आए पर्यटकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। लाइव म्यूज़िक, विशेष सजावट, सांता क्लॉज़ और फेस्टिव मेन्यू ने इन आयोजनों को यादगार बना दिया। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आए। जगमगाते क्रिसमस ट्री, सांता क्लॉज़ और सजावटी लाइट्स के बीच बच्चों और युवाओं में खास उत्साह देखा गया। फेस्टिव ऑफर्स और मनोरंजन कार्यक्रमों ने माहौल को और जीवंत बना दिया। पर्यटन के चरम सीजन के चलते शहर में बड़ी संख्या में पर्यटक मौजूद हैं। झीलों के किनारे बसे होटल, कैफे और सार्वजनिक स्थलों पर क्रिसमस का उत्सव बहुसांस्कृतिक सौहार्द की मिसाल पेश करता नजर आया, जहां स्थानीय लोग और विदेशी सैलानी एक साथ खुशियां साझा करते दिखे।

आबकारी विभाग के सभागार में ली गई सुशासन की शपथ

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 25 दिसंबर। प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप मनाया गया। सचिवालय जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजली अर्पित करते हुए प्रदेश के समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों ने सुशासन की शपथ दिलवाई। आबकारी विभाग के समस्त अधिकारी व कर्मचारी सुशासन दिवस के कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए सुशासन की शपथ ली। आबकारी आयुक्त शिवप्रसाद नकाते ने सुशासन दिवस पर भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की तस्वीर के समक्ष पुष्पांजली अर्पित की। इसके पश्चात् उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों व कर्मचारियों को राजकीय कार्य के प्रति निष्ठा, समर्पण, समयबद्धता एवं पारदर्शिता का भाव रखते हुए कुशलता से कार्य निस्तारण का संदेश दिया। आबकारी भवन उदयपुर मुख्यालय के सभागार में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में अतिरिक्त आबकारी आयुक्त प्रशासन ओपी जैन एवं अतिरिक्त आबकारी आयुक्त पॉलिसी प्रदीप सिंह सांगावत के नेतृत्व में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी को स्मरण करते हुए उनकी तस्वीर के समक्ष पुष्पांजली अर्पित की गई और सुशासन की शपथ ली गई। इस अवसर पर वित्तिय सलाहकार सुनीता विजय, जिला आबकारी अधिकारी आदराम, उपायुक्त ईपीएफ उदयपुर प्रद्युम्न सिंह चुण्डावत सहित समस्त अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

भवजीत, प्रतिज्ञा और ताशी का राष्ट्रीय रोलर स्केटिंग में चयन

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। मयंक सोनी स्केटिंग क्लब के होनहार खिलाड़ी भवजीत राजपुरोहित, प्रतिज्ञा सालवी और ताशी पुनेरा का चयन 69वीं स्कूल नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के लिए किया गया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 24 दिसंबर से ग्वालियर (मध्यप्रदेश) में आयोजित होगी, जिसमें तीनों खिलाड़ी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करेंगी। कोच मयंक सोनी ने बताया कि राज्य स्तरीय टीम चयन प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसके आधार पर चयन हुआ। क्लब के प्रशिक्षकों और अभिभावकों ने खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर बेहतरीन प्रदर्शन की शुभकामनाएं दी हैं।

चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण 26 व 27 दिसंबर को

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर, 25 दिसंबर। मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा की कांस्टेबल भर्ती विज्ञप्ति वर्ष 2025 (टीएसपी) के अंतर्गत मेवाड़ भील कोर खेरवाड़ा में कांस्टेबल (सामान्य) एवं कांस्टेबल (बैंड) के वर्गवार 106 रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। मेवाड़ भील कोर कमाण्डेन्ट निरंजन चारण ने बताया कि दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हुए 105 चयनित अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण 26 एवं 27 दिसंबर को प्रातः 7:30 बजे से स्व. हरिदेव जोशी राजकीय सामान्य चिकित्सालय, डूंगरपुर में गठित मेडिकल बोर्ड के समक्ष कराया जाएगा। सभी चयनित अभ्यर्थी शुक्रवार को निर्धारित समय पर उपस्थित होवें।

महाराणा प्रताप सेना ने बेसहारा महिला का कराया अंतिम संस्कार

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। महाराणा प्रताप सेना ने एक बार फिर सामाजिक संवेदनशीलता और मानवीय दायित्व का परिचय देते हुए बेसहारा महिला का अंतिम संस्कार कर समाज के सामने सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। महाराणा प्रताप सेना को 25 दिसंबर 2025 को आशाधाम आश्रम से सूचना मिली कि पिछले 17 वर्षों से आशाधाम में निवास कर रहीं प्रेमा का मंगलवार शाम करीब 5 बजे निधन हो गया है। आश्रम प्रशासन द्वारा विधिवत पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कराने के बाद शव महाराणा प्रताप सेना को सौंपा गया। इसके पश्चात महाराणा प्रताप सेना के सदस्यों ने अशोक नगर मोक्षधाम में पूरे विधि-विधान एवं सम्मान के साथ महिला का अंतिम संस्कार संपन्न कराया। इस सेवा कार्य में संगठन के संस्थापक मोहन सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आशाधाम आश्रम की सिस्टर डेनिसा, गजेंद्र सिंह राठौड़, नरेंद्र सिंह शक्तावत, पुष्कर वैष्णव, नंदराज भारती, सुनील मीणा, राजेंद्र कलसुआ, कांतिलाल, रूपचंद और राज थापा सहित अन्य सेवाभावी सदस्य उपस्थित रहे।

अनपढ़ उम्मीदवारों पर सियासी ब्रेक! पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बड़ा बदलाव प्रस्तावित

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। राजस्थान में अगले साल प्रस्तावित पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों से पहले सरकार एक बड़ा बदलाव करने की तैयारी में है। चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता को दोबारा अनिवार्य करने का रोडमैप लगभग तैयार हो चुका है। यदि प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी मिलती है तो अनपढ़ उम्मीदवार पार्षद से लेकर सरपंच, प्रधान, प्रमुख और मेयर जैसे पदों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सरकार के स्तर पर पंचायतीराज और शहरी निकाय—दोनों चुनावों के लिए अलग-अलग प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजे गए हैं। शहरी विकास एवं आवासन मंत्री ने निकाय चुनावों से जुड़े प्रस्ताव भेजे हैं, जबकि पंचायतीराज मंत्री ने ग्रामीण निकायों के लिए शैक्षणिक योग्यता लागू करने का मसौदा तैयार कर मंजूरी के लिए आगे बढ़ाया है। प्रस्तावों के अनुसार सरपंच पद के लिए न्यूनतम 10वीं पास होना अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। वहीं शहरी निकायों में पार्षद पद के लिए 10वीं या 12वीं में से किसी एक शैक्षणिक योग्यता को लागू करने का विकल्प रखा गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय निकायों में प्रशासनिक समझ और निर्णय क्षमता को मजबूत करना बताया जा रहा है। पंचायतीराज मंत्री मदन दिलावर उर्फ खर्रा ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक योग्यता लागू करने के लिए मौजूदा पंचायतीराज अधिनियम और नगरपालिका कानून में संशोधन करना होगा। मुख्यमंत्री स्तर से हरी झंडी मिलने के बाद दो अलग-अलग विधेयक लाए जाएंगे, जिन्हें विधानसभा के आगामी बजट सत्र में पारित कराने की तैयारी है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2015 में तत्कालीन वसुंधरा राजे सरकार ने भी पंचायतीराज और शहरी निकाय चुनावों में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। उस समय चुनाव से ठीक पहले कैबिनेट से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी ली गई थी। तब वार्ड पंच के लिए कोई शैक्षणिक बाध्यता नहीं थी, लेकिन सरपंच के लिए आठवीं पास और टीएसपी क्षेत्रों में पांचवीं पास होना अनिवार्य किया गया था। पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए 10वीं पास की शर्त लागू की गई थी, जबकि पार्षद और निकाय प्रमुखों के लिए भी 10वीं पास होना जरूरी था। हालांकि 2018 में सत्ता में आई अशोक गहलोत सरकार ने कांग्रेस के चुनावी वादे के अनुरूप 2019 में इस प्रावधान को पूरी तरह हटा दिया था। कांग्रेस ने शैक्षणिक योग्यता को जनप्रतिनिधित्व के खिलाफ बताते हुए इसका तीखा विरोध किया था। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि 2015 में शैक्षणिक योग्यता लागू होने से पंचायतीराज चुनावों में भाजपा को ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट फायदा मिला था। कांग्रेस की तुलना में भाजपा के अधिक जनप्रतिनिधि जीतकर आए थे। अब एक बार फिर भाजपा के भीतर से ही इस व्यवस्था को दोबारा लागू करने की पैरवी तेज हुई, जिसके बाद यह प्रस्ताव फिर से सरकार के एजेंडे में आया है। अब सबकी नजर मुख्यमंत्री के निर्णय और बजट सत्र में पेश होने वाले विधेयकों पर टिकी है, जो यह तय करेंगे कि आने वाले चुनावों में शिक्षा राजनीति की नई शर्त बनेगी या नहीं।

यह प्रयोग उदयपुर में भी हो सकता है क्या?? 1 स्टोर का आइडिया है बड़ा शानदार!!

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। अगर नेताओं को राजनीति, आपसी खींचतान और जमीन के लोभ लालच प्रपंचों से समय मिले, तो उदयपुर में भी एक दिन के लिए '1 स्टोर' जैसे सामाजिक प्रयोग संभव हैं। इसकी प्रेरणा मिली सकती है अगर चाहें तो, चंडीगढ़ नगर निगम के हालिया आयोजन से, जहां एक दिन के लिए स्टोर खोला गया और जरूरतमंद नागरिकों को गर्म कपड़े, जूते, किताबें और बर्तन मात्र 1 रुपए में उपलब्ध कराए गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 38 सी में आयोजित इस स्टोर में लोगों की भीड़ उमड़ी। किसी को मिक्सी मिली, किसी को जूते, और कई बच्चों ने किताबें लेकर खुशी जाहिर की। नगर निगम की मेयर हरप्रीत कौर बबला ने बताया कि यह पहल पहले भी होती रही है और इससे न केवल जरूरतमंदों को लाभ मिलता है बल्कि घरों में पड़े अनावश्यक सामान का पुनः उपयोग भी सुनिश्चित होता है। सामाजिक और प्रशासनिक माहौल में इस तरह के प्रयोग से कई लाभ संभव हैं। नगर निगम स्थानीय नागरिकों और घरों में पड़े फालतू सामान, जैसे पुराने कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और किताबें, संग्रहित कर उन्हें साफ-सुथरा कर स्टोर में रख सकता है। एक दिन के आयोजन में जरूरतमंद लोग इन वस्तुओं को 1 रुपए में ले जाकर सीधे लाभान्वित हो सकते हैं जैसा कि चंडीगढ में हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रयोग से न केवल समाज में सहयोग और आपसी समर्पण की भावना बढ़ती है बल्कि शहर में सामाजिक समानता और संसाधन पुनः उपयोग की दिशा में भी कदम बढ़ता है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों को किताबें, स्टेशनरी और अन्य आवश्यक सामान आसानी से उपलब्ध होंगे।

धरी रह गई पंचायती : जालोर में महिलाओं के मोबाइल प्रयोग पर लगाया था बैन, भारी विरोध, वापस लिया फैसला

24 न्यूज अपडेट

जालोर। समाज की चिंता के नाम पर निजी जीवन के ठेकेदार बनने की कोशिश जालोर में पंचों को भारी पड़ गई। चौधरी समाज सुंधामाता पट्टी की पंचायत द्वारा महिलाओं के स्मार्टफोन उपयोग पर लगाया गया सामाजिक प्रतिबंध विरोध की आंच में टिक नहीं सका और आखिरकार पंचों को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। सवाल अब यही है—क्या पंच समाज की मर्यादा के रक्षक हैं या रोजमर्रा की जिंदगी के फैसलों के ठेकेदार?

21 दिसंबर को गजीपुर गांव में आयोजित समाज की बैठक में पंचों ने 15 गांवों की बहू-बेटियों के स्मार्टफोन उपयोग पर रोक लगाने का फैसला सुना दिया था। घोषणा के मुताबिक 26 जनवरी से महिलाओं को स्मार्टफोन रखने की मनाही होती और उन्हें केवल की-पैड मोबाइल तक सीमित रहना पड़ता। पढ़ाई करने वाली बच्चियों को भी मोबाइल सिर्फ घर के भीतर इस्तेमाल करने की सलाह दी गई थी।

संस्कृति की आड़ में नियंत्रण की कोशिश

पंचायत ने इस फैसले को 'संस्कृति, बच्चों की आदतें और सामाजिक अनुशासन' से जोड़कर पेश किया, लेकिन बाहर आते ही यह निर्णय महिलाओं की स्वतंत्रता और निजता में दखल के रूप में देखा गया। समाज के भीतर ही सवाल उठने लगे कि मोबाइल फोन जैसे व्यक्तिगत साधन पर नियंत्रण का अधिकार पंचों को किसने दिया। महिलाओं और युवाओं के बीच इस फरमान को लेकर नाराजगी बढ़ती गई। देखते ही देखते यह मुद्दा गांव की चौपाल से निकलकर सामाजिक विमर्श का विषय बन गया।

विरोध बढ़ा तो बदला सुर

आलोचना और असहमति के बढ़ते दबाव के बाद बुधवार को गजीपुर गांव में ही 14 पट्टी गांवों के पंचों की दोबारा बैठक बुलाई गई। बैठक के बाद पहले लिए गए निर्णय को औपचारिक रूप से रद्द कर दिया गया। पंच नथाराम चौधरी ने कहा कि फैसला बच्चों की भलाई के लिए लिया गया था, लेकिन समाज ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने माना कि लोगों ने इसे महिलाओं पर प्रतिबंध के रूप में देखा, इसलिए इसे वापस लिया जा रहा है।

बच्चों की चिंता या नियंत्रण की सोच?

पंचों का तर्क रहा कि समाज की महिलाओं ने ही शिकायत की थी कि बच्चे स्कूल से लौटने के बाद मोबाइल में उलझ जाते हैं, न पढ़ाई करते हैं और न ही समय पर भोजन करते हैं। मोबाइल ऐप्स और वीडियो से बच्चों की आंखों और मानसिक स्थिति पर असर पड़ने की बात भी कही गई। इसी आधार पर सुझाव सामने आया कि घरों में स्मार्टफोन सीमित हों। लेकिन सवाल यह भी उठा कि बच्चों की आदत सुधारने का बोझ सिर्फ महिलाओं पर क्यों डाला गया और समाधान के नाम पर उन्हीं की आजादी पर रोक क्यों लगाई गई।

कटारिया को धमकी, लिखा-जहां भी मिले मारो !! जांच में जुटी पुलिस

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान के बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया एक बार फिर विवाद के केंद्र में आ गए हैं। इस बयान पर उपजे आक्रोश के बीच क्षत्रिय करणी सेना से जुड़ा एक आपत्तिजनक और धमकी भरा सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया है, जिसके बाद प्रशासन और पुलिस सतर्क हो गई है।

सोशल मीडिया पर वायरल पोस्ट में करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत के नाम से कटारिया के खिलाफ उकसाने वाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है। पोस्ट में राज्यपाल पर महाराणा प्रताप के अपमान का आरोप लगाते हुए हिंसा के लिए भड़काने जैसे शब्द लिखे गए हैं। इस पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर तीखी बहस छिड़ गई है—एक वर्ग जहां कटारिया के बयान से नाराजगी जता रहा है, वहीं दूसरा वर्ग धमकी की भाषा को लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बता रहा है।

पुलिस के संज्ञान में मामला, जांच शुरू

उदयपुर के पुलिस अधीक्षक योगेश गोयल ने बताया कि मामला पुलिस के संज्ञान में आया है और सोशल मीडिया पोस्ट की तकनीकी व कानूनी जांच की जा रही है। अभी तक राज्यपाल की ओर से कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले किसी भी कृत्य को गंभीरता से लिया जाएगा।

क्या है विवाद की पृष्ठभूमि

यह पूरा घटनाक्रम 22 दिसंबर को उदयपुर जिले के गोगुंदा क्षेत्र की धूली घाटी में हुए एक शिलान्यास कार्यक्रम से जुड़ा है। वहां अपने संबोधन में गुलाबचंद कटारिया ने कहा था कि महाराणा प्रताप का नाम पहले केवल लिया जाता था, लेकिन उन्हें वास्तविक पहचान और विकास कार्यों से जोड़ने का काम जनता पार्टी के शासनकाल में हुआ। इसी क्रम में उन्होंने हल्दीघाटी, चावंड, पोखरगढ़ जैसे ऐतिहासिक स्थलों के विकास और सड़क निर्माण का उल्लेख किया था। हालांकि, उनके भाषण में प्रयुक्त "महाराणा प्रताप को पहली बार जिंदा करने" जैसी शब्दावली को लेकर क्षत्रिय संगठनों और कई इतिहासप्रेमियों ने कड़ी आपत्ति जताई। विरोध करने वालों का कहना है कि ऐसे शब्द इतिहास पुरुषों की विरासत को राजनीतिक विमर्श में सीमित कर देते हैं।

समाज को जोड़ने की अपील भी रही भाषण में

भाषण में कटारिया ने समाज को बांटने की राजनीति पर सवाल उठाते हुए यह भी कहा था कि महाराणा प्रताप की सेना में भील समुदाय की अहम भूमिका रही और फूट डालकर राजनीति करने से देश कमजोर होता है। उन्होंने युवाओं से नशा, दिखावे और हिंसा से दूर रहकर शिक्षा, ईमानदारी और विवेक के साथ आगे बढ़ने की अपील की थी।

215 किमी तक की द्वितीय श्रेणी साधारण यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं, संशोधित किराया कल से लागू होगा

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भारतीय रेलवे ने अपने यात्री किराया ढांचे को तर्कसंगत बनाने का निर्णय लिया है। उपनगरीय सेवाओं, सीजन टिकटों और 215 किमी तक की द्वितीय श्रेणी साधारण यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। यात्रियों पर न्यूनतम प्रभाव होगाः स्लीपर और प्रथम श्रेणी साधारण के लिए प्रति किलोमीटर केवल 1 पैसा की वृद्धि की गई है। एसी और नॉन-एसी दोनों श्रेणियों में मेल/एक्सप्रेस ट्रेन के किराए में संशोधन प्रति किलोमीटर केवल 2 पैसे तक सीमित रहेगा। किराया तर्कसंगत बनाने के तहत आरक्षण शुल्क या सुपरफास्ट शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी की प्रयोज्यता और किराया राउंडिंग नियम भी अपरिवर्तित रहेंगे। संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 से बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। मौजूदा बुकिंग या भविष्य की यात्रा के टिकटों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा और परिचालन की निरंतरता के बीच संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से अपने यात्री किराया ढांचे को तर्कसंगत बनाया है। उपनगरीय और गैर-उपनगरीय दोनों मार्गों की सेवाओं और सीजन टिकटों के किराए में कोई बदलाव नहीं किया गया है। साधारण नॉन-एसी (गैर-उपनगरीय) सेवाओं के लिए, द्वितीय श्रेणी साधारण, स्लीपर श्रेणी साधारण और प्रथम श्रेणी साधारण के किराए को श्रेणीबद्ध तरीके से तर्कसंगत बनाया गया है। साधारण द्वितीय श्रेणी में 215 किमी तक की यात्राओं के लिए किराए में कोई वृद्धि नहीं की गई है। 216 किमी से 750 किमी तक की दूरी के लिए 5 की वृद्धि हुई है। इसके बाद की दूरी के लिए वृद्धि चरणबद्ध तरीके से लागू होगीः

751–1250 किमीः 10

1251–1750 किमीः 15

1751–2250 किमीः 20

साधारण स्लीपर और प्रथम श्रेणी साधारण में, गैर-उपनगरीय यात्राओं के लिए प्रति किलोमीटर 1 पैसे की वृद्धि की गई है। मेल/एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन-एसी और एसी दोनों श्रेणियों के किराए में प्रति किलोमीटर 2 पैसे की वृद्धि की गई है। इसमें स्लीपर, फर्स्ट क्लास, एसी चेयर कार, एसी थ्री-टियर, एसी टू-टियर और एसी फर्स्ट क्लास शामिल हैं। उदाहरण के लिए, नॉन-एसी मेल/एक्सप्रेस कोच में 500 किलोमीटर की यात्रा करने पर यात्रियों को लगभग 10 अतिरिक्त देना होगा। प्रमुख रेल सेवाओं, जिनमें तेजस राजधानी, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, वंदे भारत, हमसफर, अमृत भारत, तेजस, महामाना, गतिमान, अंत्योदय, गरीब रथ, जन शताब्दी, युवा एक्सप्रेस, नमो भारत रैपिड रेल और साधारण गैर-उपनगरीय सेवाएं (जहां लागू हो वहां एसी एमईएमयू/डीईएमयू को छोड़कर) शामिल हैं, के मौजूदा मूल किराए को अनुमोदित श्रेणीवार वृद्धि के अनुसार संशोधित किया गया है। यह सभी श्रेणियों में समान और क्रमबद्ध तरीके से लागू होगा। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज या अन्य सहायक शुल्कों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जीएसटी की प्रयोज्यता और किरायों का राउंडिंग नियम अपरिवर्तित रहेंगे। संशोधित किराया केवल 26 दिसंबर 2025 या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होगा। इससे पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगेगा, भले ही यात्रा प्रभावी तिथि के बाद की हो। स्टेशनों पर प्रदर्शित किराया सूची भी 26 दिसंबर 2025 से लागू नए किराए के अनुसार अपडेट की जाएगी।

राजस्थान में ट्रैक नवीनीकरण की 850 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति

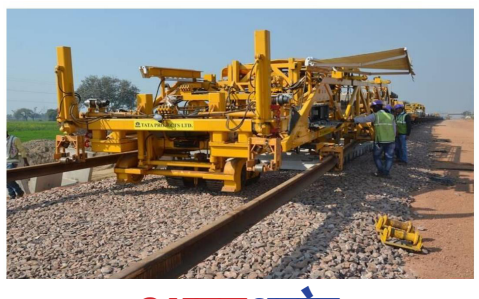

24 न्यूज अपडेट

जयपुर। भारतीय रेलवे ने देश की रेल अवसंरचना को आधुनिक बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके तहत उत्तर पश्चिम रेलवे (NWR) के अंतर्गत राई का बाग–फलोदी–जैसलमेर तथा लालगढ़–कोलायत–फलोदी रेल खंडों में व्यापक ट्रैक नवीनीकरण कार्य को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह परियोजना 850 करोड़ की लागत से क्रियान्वित की जाएगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह प्रस्ताव दो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रेल खंडों की ट्रैक संरचना को आधुनिक और मजबूत बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था। इन खंडों पर वर्तमान में पुरानी रेल पटरियाँ और स्लीपर उपयोग में हैं, जिनका नवीनीकरण सुरक्षा, परिचालन क्षमता और दीर्घकालिक रखरखाव की दृष्टि से आवश्यक माना जा रहा है। परियोजना के तहत पहला खंड राई का बाग–फलोदी–जैसलमेर है, जिसकी कुल लंबाई 291.126 किलोमीटर है। इस मार्ग पर वर्तमान में स्थापित रेल पटरियों का रोलिंग मार्क वर्ष 2005 का है, जिन्हें 2006 में बिछाया गया था। लंबे समय से परिचालन में रहे इस ट्रैक के नवीनीकरण को रेलवे प्रशासन ने तकनीकी आवश्यकता के रूप में चिन्हित किया था। इसके बाद विस्तृत सर्वेक्षण और आकलन के आधार पर यह प्रस्ताव तैयार किया गया। दूसरा खंड लालगढ़–कोलायत–फलोदी है, जिसकी कुल लंबाई 73.742 किलोमीटर है। इस खंड में उपयोग में लाई जा रही रेल पटरियों का रोलिंग मार्क 2004 से 2006 के बीच का है और इन्हें 2006–07 के दौरान बिछाया गया था। अधिकारियों के अनुसार, दोनों ही खंडों पर ट्रैक संरचना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए नवीनीकरण कार्य को प्राथमिकता सूची में शामिल किया गया था। फाइनेंस विभाग ने इस परियोजना के लिए प्रति किलोमीटर 2.84 करोड़ की लागत को पहले ही स्वीकृति दे दी थी। अधिकारियों के अनुसार, प्रस्तावित लागत और निर्धारित तकनीकी मानकों के आधार पर यह कार्य नियोजित समयसीमा के भीतर निष्पादित किया जाएगा। इस परियोजना के पूर्ण होने के बाद संबंधित मार्गों पर रेल परिचालन अधिक सुरक्षित, सुचारु और विश्वसनीय हो सकेगा, जिससे क्षेत्रीय संपर्क के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों को भी गति मिलेगी।

यूडीए की तीन आवासीय योजनाओं में 1109 भूखंड आवंटित, 43 हजार से ज्यादा आवेदकों की उम्मीदों को लगे पंख

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। राज्य सरकार की 'हमारा प्रयास, सबको आवास' संकल्पना को जमीन पर उतारते हुए उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) ने गुरुवार को झीलों की नगरी के सुनियोजित विस्तार की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया। यूडीए की तीन आवासीय योजनाओं के कुल 1109 आवासीय भूखंडों की ई-लॉटरी दक्षिण विस्तार स्थित सामुदायिक भवन में समारोहपूर्वक संपन्न हुई।

राज्य सरकार के दो वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला और भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा मुख्य अतिथि रहे। अत्याधुनिक एल्गोरिदम आधारित सॉफ्टवेयर से पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी तरीके से हुई लॉटरी ने हजारों परिवारों के अपने घर के सपने को ठोस आकार दिया।

43,361 आवेदनों में से 1109 को मिला अवसर

यूडीए की ओर से साउथ एक्सटेंशन सेक्टर-ए (सवीना खेड़ा), उद्यम विहार (कलड़वास) और नान्देश्वर एनक्लेव (नोहरा) आवासीय योजनाओं के लिए 7 अक्टूबर से 17 नवंबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इन तीनों योजनाओं के लिए कुल 43,361 आवेदन प्राप्त हुए। साउथ एक्सटेंशन के 550 भूखंडों के लिए 28,079 आवेदन, उद्यम विहार के 311 भूखंडों के लिए 9,530 आवेदन, नान्देश्वर एनक्लेव के 248 भूखंडों के लिए 5,752 आवेदन आए। भारी प्रतिस्पर्धा के बीच ई-लॉटरी के जरिए चयन ने प्रक्रिया को निष्पक्ष और विश्वसनीय बनाया।

ई-लॉटरी सुशासन का सशक्त उदाहरण

मुख्य अतिथि मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह स्वचालित, ऑनलाइन और एल्गोरिदम आधारित है, जिसमें किसी भी स्तर पर मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया। इससे सभी पात्र आवेदकों को समान अवसर मिलता है। उन्होंने ई-लॉटरी को सुशासन का श्रेष्ठ उदाहरण बताते हुए कहा कि पारदर्शी व्यवस्थाओं से आमजन का सरकारी तंत्र पर भरोसा मजबूत होता है। उन्होंने सफल आवंटियों को शुभकामनाएं दीं और कहा कि राज्य सरकार व यूडीए भविष्य में भी आमजन के लिए नई आवासीय योजनाएं लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

आवेदकों की भागीदारी से तय हुआ एल्गोरिदम

लॉटरी प्रक्रिया की शुरुआत मंत्री खर्रा सहित अतिथियों द्वारा रिमोट बटन दबाकर पोर्टल ऑन करने से हुई। प्रत्येक योजना में ईडब्ल्यूएस, अल्प आय वर्ग, मध्यम आय वर्ग और उच्च आय वर्ग के साथ-साथ एससी, एसटी, दिव्यांग, राजकीय कर्मचारी, अधिस्वीकृत पत्रकार, ट्रांसजेंडर सहित 9-9 उपश्रेणियों में आवंटन किया जाना था।

प्रत्येक श्रेणी के लिए आवश्यक 4-डिजिट एल्गोरिदम कार्यक्रम स्थल पर मौजूद आवेदकों से ही लिया गया, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और सहभागिता सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम स्थल के मुख्य हॉल, समीपस्थ हॉल और बाहरी परिसर में बड़ी-बड़ी स्क्रीन पर लॉटरी का सीधा प्रसारण किया गया। हर आवंटन के बाद जिला प्रशासन द्वारा नियुक्त समिति के हस्ताक्षरयुक्त सूची सूचना पट्ट पर चस्पा की गई और साथ ही यूडीए की वेबसाइट पर अपलोड की गई।

जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की मौजूदगी

कार्यक्रम में उदयपुर ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवलरमानी, पूर्व विधायक वंदना मीणा, यूआईटी के पूर्व अध्यक्ष रविन्द्र श्रीमाली, एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा, बड़गांव एसडीएम लतिका पालीवाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। यूडीए आयुक्त राहुल जैन और सचिव हेमेंद्र नागर ने अतिथियों का स्वागत करते हुए योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।

मातृभूमि और कर्मभूमि में समानांतर सेवा कार्य करने वाले भामाशाह पारस चपलोत को मिला अटल सम्मान

24 न्यूज अपडेट

निम्बाहेडा (कविता पारख)। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ऐतिहासिक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में द्वादशभरा-त्रिवर्षीय अटल सम्मान समारोह व प्रसिद्ध संगीतमय अटल गाथा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन अटल सम्मान समारोह ट्रस्ट द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध कथा वाचक अजय भाई ने संगीतमय अटल गाथा का आयोजन कर लोगों का दिल जीत लिया। उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन को उनकी कविताओं और स्मृतियों का संगीतमय पाठ कर लोगों का खूब मन मोह। इस अवसर पर विशेष रूप से अटलजी के विशिष्ट सहयोगी पूर्व सांसद और पूर्व कैबिनेट मंत्री सत्यनारायण जटिया की प्रमुख उपस्थिति में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने जीवदया प्रेमी, समाजसेवी तथा देश-विदेश में कारोबार का डंका बजाने वाले पारस चपलोत को अटल सम्मान से विभूषित किया। अटल सम्मान समारोह की अध्यक्षता ट्रस्ट के संरक्षक सांसद मनोज तिवारी ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सभी चयनित लोगों को अटल सम्मान प्रदान किए। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू, प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, दिल्ली विधानसभा मुख्य सचेतक प्रतिपक्ष अजय महावर, प्रसिद्ध समाजसेवी सत्यभूषण जैन, राष्ट्रीय कवि संगम के अध्यक्ष जगदीश निताल, अटल सम्मान समारोह के संरक्षक रोशन कंसल, वाइस चेयरमैन नवीन तायल ने आने वाले सभी अतिथियों का स्वागत सत्कार किया तथा सभी अवॉर्डियों के जीवन कार्यों पर प्रकाश डाला। कुल 17 देश-विदेश की हस्तियों को अटल सम्मान से अलंकृत किया गया। बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के पारस चपलोत मूल निवासी ग्राम पंचायत बाड़ी तहसील निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ के होकर हॉल मुकाम भंयदर में परिवार सहित रह कर धार्मिक कार्यक्रमों के साथ ही कोरोना दिवसों सहित समाजसेवा में, जीवदया में, आदि अन्य कई संगठनों में अपना काफी योगदान करते हुए सहयोग करते रहते हैं।

अटल जयंती पर प्रतिभा का सम्मान, राज्यपाल कटारिया ने विद्यार्थियों को दिया राष्ट्रसेवा का संदेश

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म जयंती को उदयपुर में शिक्षा और प्रेरणा के उत्सव के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर श्री सुन्दरसिंह भण्डारी चेरिटेबल ट्रस्ट, उदयपुर की ओर से प्रतिभावान छात्र-छात्रा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह 25 दिसंबर को सुखाड़िया रंगमंच, टाउन हॉल, उदयपुर में आयोजित हुआ, जिसमें पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम में शहर के गणमान्य नागरिकों, शिक्षाविदों, अभिभावकों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की बड़ी उपस्थिति रही। मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए राज्यपाल कटारिया ने स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन और विचारों को स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अटल जी का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण, सुशासन की सोच और दूरदर्शी नेतृत्व आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे केवल शैक्षणिक उपलब्धियों तक सीमित न रहें, बल्कि अपने जीवन में संस्कार, अनुशासन और राष्ट्रसेवा को भी समान महत्व दें। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों के मेधावी छात्र-छात्राओं को उनकी उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया गया। चयनित विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका उत्साहवर्धन किया गया।

कटारिया बोले - मंत्री महोदय कहां हो, क्या हो रहा है...हमारा टीचर क्या कर रहा है?

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। समारोह के मंच से पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर तीखी और बेबाक टिप्पणी कर दी। आदिवासी अंचलों के सरकारी स्कूलों में कमजोर शैक्षणिक प्रदर्शन पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जहां-जहां स्कूलों के परिणाम खराब हैं, वहां जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मंच से ही उन्होंने जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी की ओर देखते हुए कहा— "मंत्री महोदय कहां हो, क्या हो रहा है हमारा टीचर क्या कर रहा है?" कटारिया का यह बयान सुनते ही सभागार में मौजूद जनप्रतिनिधियों और अतिथियों के बीच हल्की मुस्कान और ठहाकों का माहौल बन गया, लेकिन संदेश बेहद गंभीर था—शिक्षा में लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं। दरअसल, राज्यपाल उदयपुर के टाउन हॉल में सुंदर सिंह भंडारी चेरिटेबल ट्रस्ट की ओर से आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंच पर उनके साथ यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, सांसद मन्नालाल रावत, विधायक ताराचंद जैन, फूलसिंह मीणा, शांता मीणा, प्रताप गमेती और उदयलाल डांगी मौजूद थे। अपने संबोधन के दौरान कटारिया विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक आंकड़े साझा कर रहे थे। उन्होंने बताया कि कई क्षेत्रों से 90 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले बड़ी संख्या में विद्यार्थी सामने आए हैं, लेकिन जब झाड़ोल क्षेत्र की बात आई तो उन्होंने चिंता जताई कि वहां से केवल दो ही विद्यार्थी इस श्रेणी में आए हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने शिक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़े किए और जनजाति मंत्री की ओर देखकर यह टिप्पणी की। सम्मान समारोह में कुल 390 विद्यार्थियों और 33 संस्था प्रधानों को सम्मानित किया गया। आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक 107 विद्यार्थी वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र से रहे, जबकि सबसे कम विद्यार्थी झाड़ोल विधानसभा से चयनित हुए। कटारिया ने कहा कि बच्चों की मेहनत पूरे समाज के लिए प्रेरणा है। उन्होंने यह भी माना कि आज भी गांवों में समर्पित शिक्षक मौजूद हैं और सरकारी विद्यालयों से पढ़कर 95 और 99 प्रतिशत अंक लाने वाले विद्यार्थी जिले की ताकत हैं। उन्होंने विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्रों की बेटियों की सफलता को उल्लेखनीय बताते हुए कहा कि यह हमारी असली प्रतिभा है। राज्यपाल ने भरोसा दिलाया कि इन बच्चों को आगे बढ़ाने और उनका भविष्य संवारने के लिए हरसंभव प्रयास किए जाएंगे, लेकिन इसके लिए पहले व्यवस्था और सोच में बदलाव जरूरी है। कार्यक्रम में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने भी विद्यार्थियों को संबोधित किया। उन्होंने बच्चों से बेहतर शिक्षा हासिल कर राष्ट्र सेवा के लिए आगे आने का आह्वान किया और कहा कि सरकार पाठ्यक्रम और शिक्षा प्रणाली में सुधार कर इसे और मजबूत बना रही है।

भोजन को रोका तो हो गई बहस, चले गए

कार्यक्रम समाप्त होने के बाद टाउन हॉल परिसर में उस समय माहौल गर्मा गया, जब राज्यपाल और मंत्रियों के साथ भोजन के लिए जा रहे कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों को प्रवेश से रोका गया। इस बात को लेकर आयोजन से जुड़े पदाधिकारियों और कर्मचारी नेताओं के बीच तीखी बहस हो गई। कर्मचारी नेता कमल बाबेल सहित करीब एक दर्जन लोगों ने नाराजगी जताते हुए विरोध किया और बाद में सभी वहां से चले गए। उनका कहना था कि वे भी अलग से बनाए गए वीआईपी एरिया में जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्हें रोका गया।

इस पूरे घटनाक्रम ने जहां शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए, वहीं कार्यक्रम के बाद का विवाद भी चर्चा का विषय बन गया।

सिन्धी समाज का क्रिकेट महाकुंभः जेपीएल सीजन–4 का धमाकेदार शुभारम्भ

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। सिन्धी सेन्ट्रल युवा सेवा समिति के कुशल नेतृत्व में आयोजित जेपीएल (झुलेलाल प्रीमियर लीग) सीजन–4 का उद्घाटन समारोह उदयपुर में अत्यंत उत्साह, खेलभावना और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। पहले दिन का खेल स्वर्गीय भानु कुमार शास्त्री की स्मृति को समर्पित रहा, जिससे टूर्नामेंट ने सम्मान और खेल दोनों का संदेश एक साथ दिया। समिति अध्यक्ष विजय आहूजा ने बताया कि उद्घाटन अवसर पर शहर विधायक ताराचंद जैन, रविन्द्र श्रीमाली, सिन्धी समाज के अध्यक्ष प्रताप राय चुग, सुखराम दास, उमेश मनवानी, अशोक गेरा, किशोर झांबानी, सुरेश कटारिया, मनोज कटारिया, प्रकाश फुलानी, भगवान दास छाबड़ा समेत शास्त्री परिवार के सदस्य उपस्थित रहे। सभी अतिथियों ने टॉस कर प्रतियोगिता का विधिवत शुभारम्भ किया।

पहले दिन के मुकाबलेः रोमांच और जोश का अद्भुत मिश्रण

महासचिव मुकेश खिलवानी ने बताया कि पहले दिन कुल 5 रोमांचक मुकाबले खेले गए। इन मुकाबलों में मोहन ट्रेडिंग कम्पनी, संजय गिलास, मनसा पूर्ण करनी माता रोपवे, पृथ्वीराज मौर्या और एवरा फाइन की टीमों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और जीत अपने नाम की। मैदान पर खिलाड़ियों का उत्साह, दर्शकों की भीड़ और खेल की जीवंतता ने उत्सव को और भी खास बना दिया। उपाध्यक्ष राजेश खत्री ने बताया कि गुरुवार को होने वाले दूसरे दिन के मुकाबले स्वर्गीय प्रभुदास पाहुजा की स्मृति को समर्पित किए जाएंगे।

समाजसेवा और युवा सहभागिता का संगम

टूर्नामेंट के सफल आयोजन में मनीष डेमला, मुकेश गखरेजा, अमन असनानी, शैलेश कटारिया, जितेंद्र कालरा, कपिल मनवानी, पवन आहूजा, नानक लुंज, भावेश तलदार, चन्दप्रकाश मंगवानी सहित कई समाजसेवियों का उल्लेखनीय सहयोग रहा। जेपीएल सीजन–4 केवल खेल का मंच नहीं है, बल्कि समाज में भाईचारे, एकता और युवा सहभागिता को भी मजबूती देने वाला प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। हर मुकाबला केवल रन और विकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि सिन्धी समाज की सांस्कृतिक एकता और युवा ऊर्जा का जीवंत उत्सव बनकर सामने आया है।

मोरिया बोल गया, नेता जेल गया

24 न्यूज अपडेट

उदयपुर। डोटासरा अक्सर मोरया बोलने की बात कहते हैं। उनकी ही पार्टी के नेता का मोरया बोल गया और वो जेल गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर के शिकार के मामले में गिरफ्तार कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित तीनों आरोपियों को पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर बुधवार को न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के आदेश दिए। मामले की जांच कर रही ऋषभदेव थाना पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर जंगल क्षेत्र से मोर के पैर और पंख बरामद किए हैं। थानाधिकारी हेमंत अहारी के अनुसार पूछताछ में आरोपियों ने दावा किया कि उन्होंने पहली बार मोर का शिकार किया है, लेकिन पुलिस को उनके इस बयान पर संदेह है। घटना के बाद से जंगल और आसपास के वन क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी गई है। यह मामला 21 दिसंबर का है। ऋषभदेव थाना क्षेत्र के बीलख गांव में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल के खेत पर मोर का शिकार कर उसे पकाकर खाने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि खेत पर नॉनवेज पार्टी चल रही है, जिसमें मोर का मांस इस्तेमाल किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर दबिश दी। खेत में बने एक कमरे में तीनों आरोपी मौजूद थे, जहां पार्टी की तैयारी चल रही थी। पुलिस ने मौके से ही कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रूपलाल, हिस्ट्रीशीटर अर्जुन मीणा और उसके साथी राकेश मीणा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार अर्जुन मीणा के खिलाफ 50 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें 16 से ज्यादा प्रकरण राजस्थान में दर्ज बताए गए हैं। घटना की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने शव और अवशेषों की जांच कर मोर के शिकार की पुष्टि की। सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे गए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने नॉनवेज पार्टी के उद्देश्य से मोर का शिकार कर उसका मांस पकाने की तैयारी की थी। पुलिस और वन विभाग मामले की संयुक्त रूप से जांच कर रहे हैं।

24 न्यूज़ अपडेट- डिजिटल संस्करण स्वामित्व एवं प्रसारण ग्रुप के लिए करण सिंह देवड़ा द्वारा ई-न्यूज पेपर के फारमेट में प्रसारित प्रधान सम्पादक - सुशील जैन फोन .88520 73787, desk24newsupdate@gmail.com सर्वविवादों का न्याय क्षेत्र उदयपुर रहेगा ।